(3) बोर्ड को प्रत्येक वर्ष मौसम शुरू होने से पहले प्रत्येक राज्य से गन्ना उत्पादन की लागत के अनुमान मंगाने चाहिए और ये अनुमान उनके राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों अथवा ऐसे संस्थानों की सिफारिशों पर आधारित होने चाहिए जिन्हें राज्य सरकार इस काम के लिए उचित समझती है।

(4) राज्य सरकारों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को गन्ने की उपज की लागत की संगणना करनी चाहिए जिसे लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य का हिसाब लगाने के लिए उपयोग करने हेतु गन्ने का सैद्धान्तिक मूल्य निर्धारित करने के लिए आधार बनाया जाना चाहिए।

(5) बोर्ड को उाज की राज्यवार लागत और प्रतिस्पर्धी फसलों से सम्भावित प्राप्ति, पिछले मौसम में वास्तव में भुगतान किया गया मूल्य, मूल्य प्रवृत्ति, पिछले मौसम के दौरान चीनी की बिक्री से प्राप्ति आदि को हिसाब में लेना चाहिए और तत्पश्चात् राज्यवार/जोनवार गन्ने के वास्तविकता से पूर्ण मूल्य निर्धारित करने चाहिए जो उस राज्य/जोन के गन्ना उत्पादकों को गन्ने की अपनी प्रथम किस्त की आपूर्ति करने के बाद देय होती है। यह मूल्य उस राज्य में 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से जुड़ा होता है जिसमें ऐसी प्रक्रिया प्रचलित है जबकि जिन अन्य राज्यों में एकमुश्त मूल्य का भुगतान किया जाता है उन में मूल्य एकमुश्त आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं।

(6) दोहरी मूल्य प्रणाली जारी रखी जा सकती है जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्म पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली चीनी की विशिष्ट मात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(7) अन्त में, मौसम समाप्त होने पर बोर्ड को राज्यवार/जोनवार उस मौसम के के दौरान प्राप्त की गई औसत प्राप्तियों पर विचार करना चाहिए और प्रत्येक राज्य/जोन के लिए गन्ने का अन्तिम मूल्य निर्धारित करना चाहिए ताकि इसके अन्तर को उस राज्य/जोन में गन्ने के मूल्य की अतिरिक्त और अन्तिम किस्त के रूप में भुगतान किया जा सके।

समिति का यह भी मत था कि उपर्युक्त प्रावधानों को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में उपयुक्त संशोधन करके सांविधिक समर्थन दिया जा सकता है।

Report Submitted by High Level Committee on Price Policy

6300. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a high level committee, set up by the Centre to recommend price policy for States, has submitted its report;

(b) if so, what are the salient features thereof; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI JIT SINGH): (a) Yes, Sir. Pursuant to the decision taken in the Conference of State Sugar Ministers on 5.2.1994, a Committee of Ministers of Five States namely Uttar Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Maharashtra and Karnataka was constituted to recommend the pricing policy for State Advised Prices (SAP) of sugarcane. The Committee submitted its report on 3.4.1995.

(b) The recommendations of the aforesaid Committee of Ministers are enclosed as Statements. (*See* below)

(c) Another Conference of State Sugar Ministers was convened on 6th May, 1995 to consider the recommendations of the Committee. Though majority of the States/UTs supported the formation of a National Pricing Board, there was difference of opinion about its terms of reference. The Government has decided to seek detailed suggestions/proposals from the State Governmnts/Union Territories in this regard so that a final view can be taken.

Statement

Recommendations of the Committee of the Ministers of five State Governments constituted to make recommendations regarding pricing policy for State Advised Prices (SAP) on sugarcane.

(i) The Bhargava formula existing in its present form in the Sugarcane Control Order, 1996 should be rescinded.

(ii) A National Pricing Board for sugarcane should be constituted whose Chairman will be appointed by the Government of India and it should consist of the representatives of important cane growing States as also the Ministeries of Food, Civil Supplies and Agriculture of the Government of India.

(iii) The Board should each year before the start of the season call for from each State Government estimates of the cost of production of sugarcane based on the recommendations of the Agricultural Universities of their State or such other Institutions as the State Government may deem fit.

(iv) Taking into account the recommendations of the State Government the Board should compute the cost of cultivation of sugarcane which should form the basis for fixing a national cane price to be utilised for the calculation of retail issue price of levy sugar.

(v) The Board should take into account the State-wise cost of cultivation and the likely returns from competing crops, the price actually paid in the previous season, price trend, realisations from sale of sugar during last season etc. and thereafter fix a realistic price of cane, statewise/Zonewise which shall be payable to the cane growers of that State/Zone after supply of their cane as first instalment. This price should be linked to basic recovery of 8.25 per cent in the States in which such practice is in vogue, where as in other State where lumpsum price is paid, the price could be fixed on lumpsum basis.

(vi) The dual pricing system may continue which should ensure a specified quantum of sugar to be supplied through the Public Distribution System at a reasonable price to the consumer.

(vii) Lastly, the Board after the close of the season should consider the average realisations achieved during that season Statewise/Zonewise and fix a final cane price for State/Zone so that difference could be paid as additional and final instalment of the cane price in that State/Zone.

The Committee also felt that the aforesaid provisions could be given statutory backing by suitable modifications in the Sugarcane (Control) Order, 1966.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा विभिन्न राज्यों को चीनी की आपूर्ति

6801. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूल चन्द मीणा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विभिन्न प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित की जा रही शक्कर की मात्रा किस वर्ष की जनसंख्या पर आधारित है;

(ख) क्या जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रदेशों को इसका आबंटन बढ़ाया जाएगा; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश को उसकी जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम शक्कर उपलब्ध करायी जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (ग) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अन्तर्गत अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के मासिक आबंटन एकरूप मानकों के आधार पर किए जा रहे हैं जिससे 1-10-1986 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके । यह मानदंड 1-2-1987 से लागू हैं । तथापि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वहां पर स्थित विशेष स्थिति को देखते हुए अधिक पैमाने पर आबंटन